(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्तियों को चोटें आई तथा कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ग) इनमें मरने वाले व्यक्तियों के परिवारों को कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) पिछले तीन महीनों के दौरान 3 सुपरफास्ट गाड़ियां, 24 मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां तथा 30 पैसेंजर गाड़ियां दुर्घटनाग्रसत हुई।

(ख) इन दुर्घटनाओं में 67 व्यक्ति मारे गए और 152 व्यक्तियों को चोटें आई।

(ग) अनुग्रह राशि के रूप में 1,59,000 रु० का भुगतान किया गया है।

(घ) दुर्घटनाओं में कमी करने के लिए किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:—

(1) मानवीय तत्व की सहायता के लिए तकनीकी उपकरणों का उपयोग करना।

(2) ड्राइवरों, गार्डों, स्टेशन मास्टरों, आदि जैसी नाजुक संरक्षा कोटि के कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन पर नजर रखना।

(3) परिचालनिक कोटियों के कर्मचारियों को गहन प्रशिक्षण देना।

(4) संवेदनशील संस्थापनाओं का गहन और बार-बार निरीक्षण।

(5) बिना चौकीदार वाले सम्पारों के पहुंच मार्गों पर सिटी बोर्डों/गति अवरोधकों और सड़क संकेतों की व्यवस्था तथा सड़क उपयोगकर्ताओं और गाड़ी ड्राइवरों की दृश्यता में सुधार करना; और

(6) परिसंपत्तियों के अनुरक्षण पर नजर रखना।

Guardless Trains

397. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Indian Railways are shortly introducing "guardless trains"; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) There is no proposal at present to introduce guardless trains on the Indian Railways.

(b) Does not arise.

Rail length in Tripura

398. SHRI SUDHIR RANJAN MAJUMDAR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what is the total rail length in Tripura *viz-a-viz* in other states; and

(b) whether Government are aware that new industries could not be set up in Tripura because of poor rail link; and if so, the manner in which Government propose to solve the problem?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) A statement is attached, *[see* below]

(b) Government is quite aware of the constraints to the industrial development of backward areas. Following two schemes have been evolved to tackle the problem:—

(1) Setting up a Growth Centre at Maujas Uttar Champamura in District Tripura (West). A sum of Rs. 50 lakhs has been released as Central Assistance for the Growth Centre.

(2) 90% transport subsidy is available for the entire North East States including Tripura for movement of raw materials and 50% for movement of finished goods from one State to another State within the NE Region by road/rail/ship; and 75% for movement of electronic components/products by air from Calcutta to the airport nearest to the location of Industrial unit in the NE Region and thereafter by road/rail as stated above and *vice-versa.*